

भारत की असमानता दूर करने की मुहिम में उपलब्धियाँ: एक विस्तृत विश्लेषण

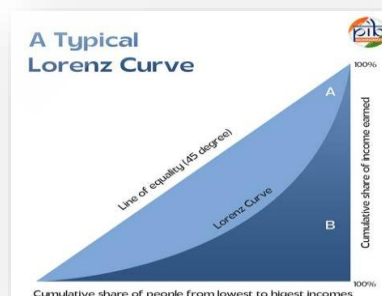
परिचय:

- भारत, एक विशाल और विविधता से भरपूर देश, ने न केवल अपने आर्थिक विकास को बढ़ाया है बल्कि समाज में असमानता को कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाल ही में, विश्व बैंक के अध्ययन ने यह प्रमाणित किया है कि भारत अब दुनिया के सर्वाधिक समतामूलक देशों में से एक है। इसके अनुसार, भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, जो इसे अन्य देशों के मुकाबले एक बेहतर स्थिति में रखता है। इस गिनी स्कोर के साथ भारत का स्थान विश्व के चौथे सबसे समतामूलक समाज के रूप में आया है। यह उपलब्धि न केवल भारत की समग्र आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है बल्कि इसके व्यापक सामाजिक समावेशन प्रयासों को भी उजागर करती है।



गिनी सूचकांक और आय समानता:

- गिनी सूचकांक, जो कि आय असमानता को मापने का एक साधारण तरीका है, 0 से 100 के बीच होता है। 0 का मतलब है पूर्ण समानता, जबकि 100 का मतलब है कि केवल एक व्यक्ति के पास पूरी आय है और अन्य सभी के पास कुछ भी नहीं।



- भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, जो यह दर्शाता है कि देश में आय का वितरण अपेक्षाकृत समान है। यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर चीन (35.7) और अमेरिका (41.8) से बहुत कम है, जो इसका एक सकारात्मक संकेत है कि भारत में आर्थिक समानता तेजी से बढ़ी है।



भारत की सामाजिक समावेशन रणनीतियाँ:

- भारत सरकार ने न केवल आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए कई प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों तक समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

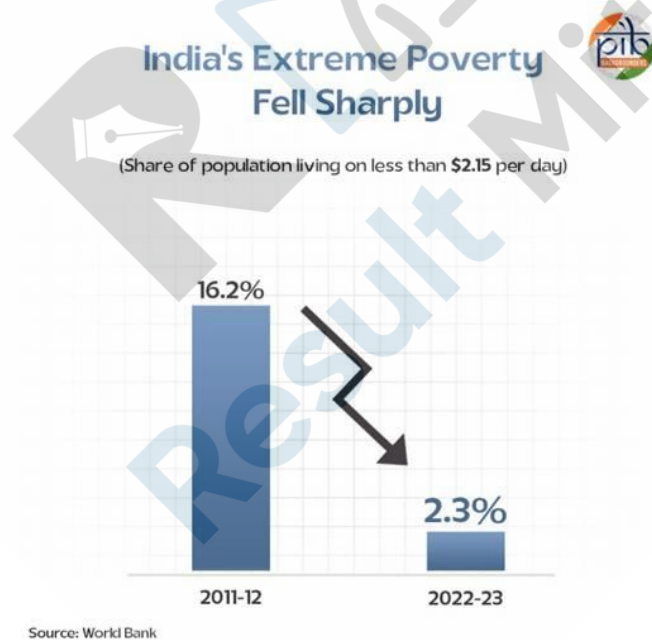
मुख्य योजनाएँ:

- 1. प्रधानमंत्री जन धन योजना: इस योजना के तहत 55.69 करोड़ से अधिक लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़े, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला।
- 2. आधार और डिजिटल पहचान: 3 जुलाई 2025 तक 142 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए हैं, जो सरकारी लाभों के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।
- 3. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी): यह प्रणाली सरकारी लाभों के वितरण को सीधा और पारदर्शी बनाती है, जिससे ₹3.48 लाख करोड़ की बचत हुई है।
- 4. आयुष्मान भारत योजना: इस योजना के तहत 41.34 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, जो स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बेहतर बनाता है।

- 5. स्टैंड-अप इंडिया योजना: 3 जुलाई 2025 तक, एससी/एसटी और महिला उद्यमियों को ₹62,807.46 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है।
- 6. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई इस योजना ने 80.67 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया।

गरीबी में कमी और समता में वृद्धि:

- भारत ने 2011-23 के बीच 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला। अत्यधिक गरीबी की परिभाषा के अनुसार, जो लोग प्रतिदिन \$2.15 से कम पर जीवन यापन करते हैं, उनकी संख्या में कमी आई है। 2011-12 में यह संख्या 16.2% थी, जो 2022-23 में घटकर केवल 2.3% रह गई। यह आंकड़ा भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता की दिशा में किए गए निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।



वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान:

- भारत का गिनी सूचकांक 25.5 इसे "सामान्य से कम" असमानता श्रेणी में रखता है। इस श्रेणी में केवल 30 देश ही आते हैं, जिनमें यूरोपीय देशों जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, और फ़िनलैंड, साथ ही बढ़ती अर्थव्यवस्थाएँ जैसे पोलैंड और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। भारत का स्थान इस श्रेणी में दर्शाता है कि देश ने समाज के विभिन्न वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

सरकारी योजनाओं का प्रभाव:

- भारत सरकार की योजनाओं ने न केवल गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की, बल्कि आर्थिक विकास के अवसर भी उत्पन्न किए हैं। विशेषकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी कम करने में इन योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आर्थिक सुधारों और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन:

- भारत का यह मॉडल यह दर्शाता है कि आर्थिक सुधार और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना संभव है। जन धन, डीबीटी और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने में मदद की है। साथ ही, स्टैंड-अप इंडिया और पीएम विश्वकर्मा योजना जैसे कार्यक्रमों ने सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है।

निष्कर्ष:

- भारत ने अपनी नीति और योजना के माध्यम से असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिनी सूचकांक में सुधार, गरीबी में कमी, और समावेशी योजनाओं की सफलता यह दर्शाती है कि आर्थिक विकास और सामाजिक समानता एक साथ हो सकती हैं। भारत का यह उदाहरण दुनिया के सामने एक प्रेरणा है कि जब ठोस नीति और समावेशी इरादे के साथ कार्य किया जाए, तो सामाजिक और आर्थिक समानता को हासिल किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे और कोई भी पीछे न छूटे।

